



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

10/7/97

सं० 418]
No. 418]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 25, 1997/श्रावण 3, 1919
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 25, 1997/SRAVANA 3, 1919

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना सं. 9/1997—2002

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1997

का. आ. 527(अ) :—सा. आ. सं. 283(अ), दिनांक 31-3-97 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-3, उपखण्ड(ii) में प्रकाशित निर्यात-आयात नीति, 1997—2002 के पैराग्राफ 1.3 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा निर्यात-आयात नीति, 1997—2002 में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

1. पैराग्राफ 8.32 को ठीक करके इस प्रकार पढ़ा जाएगा :—

“8.32 संबंधित निर्यात संवर्धन जोन/निर्यातोन्मुख एकक के विकास आयुक्त द्वारा वैध आर ई पी/हीरा अग्रदाय लाइसेंस धारक को आयात के मूल्य के 5% तक समाप्त स्टॉक या टूटे पत्थरों/अपरिष्कृत हीरों स्वदेशी रूप से प्राप्त की गई ऐसी मदों के पुनः निर्यात/आपूर्ति की अनुमति दी जाएगी।”

2. पैराग्राफ 8.36 को संशोधित करके इस प्रकार पढ़ा जाएगा :—

“8.36 निर्यातोन्मुख एककों/निर्यात संवर्धन जोन के एककों को घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में पिछले वर्ष के निर्यात के मूल्य के 10% तक बेचने की भी अनुमति होगी बशर्ते खरीददार निर्यातोन्मुख एककों/निर्यात संवर्धन जोन के एककों से इन मदों की निकासी के लिए मुक्त रूप से हस्तांतरणीय विशेष आयात लाइसेंस प्रस्तुत करें और लागू शुल्क का भुगतान खरीददार या ई ओ यू/ई पी जेड एककों के ई ई एफ सी खाते से मुक्त विदेशी मुद्रा में किया जाए। तथापि, यह आपूर्ति निर्धारित मूल्य परिवर्धन प्राप्त करने की शर्त के अधीन होगी।”

3. पैराग्राफ 12.9 में, दूसरे वाक्य “ऐसे प्रमाणपत्र की अवधि समाप्त होने पर स्तर प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए छह महीने के भीतर आवेदन करना होगा” को संशोधित करके इस प्रकार पढ़ा जाएगा :—

“ऐसे प्रमाणपत्र की अवधि समाप्त होने पर, स्तर प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर आवेदन करना होगा।”

इसे लोक हित में जारी किया जाता है।

[फाइल सं. पी आर यू/एस/97098/बी एण्ड जे]

एस. बी. महापात्र, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION No. 9/1997—2002

New Delhi, the 25th July, 1997

S. O. 527(E) :—In exercise of powers conferred by section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) read with paragraph 1.3 of the Export and Import Policy, 1997—2002 published in the Gazette of India Extraordinary, Part-II-Section 3-Sub-section (ii) *vide* S.O. No. 283(E) dated 31-3-97, the Central Government hereby makes following amendments in the Export and Import Policy, 1997—2002 :

1. The paragraph 8.32 shall be corrected to read as follows :

“8.32 Re-export/supply of dead-stock or broken stones/rough diamonds upto 5% of the value of import/indigenously procured such items to holder of valid REP/Diamond Imprest Licence may be allowed by the Development Commissioner of the EPZ/EOU concerned.”

2. The paragraph 8.36 shall be amended to read as follows :

“8.36 EOU/EPZ units are also permitted to sell 10% of value of exports of the preceding year to DTA provided the recipient furnishes a freely transferable Special Import Licence for clearance of such item from EOU/EPZ units and applicable duty is paid in free foreign exchange from the EEFC account of either the buyer or the EOU/EPZ units. Such supply shall, however, be subject to the achievement of prescribed value addition.”

3. In the paragraph 12.9, the second sentence “On the expiry of such certificate, application for renewal of status certificate shall be required to be made within a period of six months.” shall be amended to read as under :

“On the expiry of such certificate, application for renewal of status certificate shall be required to be made within the period as prescribed in Handbook of Procedures (Vol.I).”

This issues in public interest.

[F. No. PRU/AS/97098/G&J]

S. B. MOHAPATRA, Director General of Foreign Trade